



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]
No. 91]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 2008/फाल्गुन 27, 1929
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 2008/PHALGUNA 27, 1929

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(खाद्य एवं पोषण बोर्ड)

संकेत

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2008

सं. 6-5/2005-एन.डी./टैक.—I. प्रस्तावना.—पोषाहारीय स्थिति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विकास का संसूचक माना जाता है। पोषण विकास प्रक्रिया का निवेश भी है और परिणाम भी। कामगारों का स्वस्थ और सुपोषित होना सफल आर्थिक एवं सामाजिक विकास की पहली शर्त है और इस प्रकार खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई विकास संबंधी सभी क्षेत्रों का दायित्व है।

पोषण अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का एक लम्बा और गौरवशाली इतिहास रहा है। तथापि, सभी संसूचकों के अनुसार भारत में चिरकालिक, स्थान-विशिष्ट कुपोषण और खराब स्वास्थ्य की समस्या में कोई कमी नहीं आई है। देश में विभिन्न क्षेत्र पोषण के संबंध में अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिनका लोगों की पोषाहारीय स्थिति पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तथापि, कमजोर वर्गों में कुपोषण का स्तर अत्यधिक है, जो कि अस्वीकार्य है। इन कमजोर वर्गों में छोटे बच्चे, गर्भवती और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं। इन वर्गों में कुपोषण का अलग-अलग स्तर देश में रूढ़ता और मृत्यु दरों को बढ़ाता है, जिससे देश का विकास प्रभावित हो रहा है। अतः, पोषण राष्ट्रीय विकास की सबसे पहली शर्त है।

पूरक एवं संरक्षक खाद्य पदार्थों के विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाने; पोषण, खाद्य विस्तार एवं खाद्य प्रबंधन; खाद्य परिरक्षण; संसाधन और तत्संबंधी अन्य मामलों अथवा पोषाहारीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूल कार्यक्रमों के तीव्र, समन्वित एवं कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कृषि

मंत्रालय में वर्ष 1964 में दिनांक 24-4-1964 के संकल्प संख्या 6(10) 63-टैक. I के अनुसार, केन्द्र सरकार के विभाग की सभी शक्तियों से संपन्न [वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग डायरी सं. 2003-जे. एस. (एफ एण्ड ए)/64, दिनांक 20 मई, 1964] खाद्य एवं पोषण बोर्ड का गठन किया। खाद्य एवं पोषण बोर्ड (गैर-योजना अवसंरचना) वर्ष 1993 में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया।

खाद्य एवं पोषण बोर्ड को समय-समय पर पुनर्गठित किया जाता रहा है और उस समय की जरूरतों के अनुरूप बोर्ड के कृत्यों को भी पुनर्परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय पोषण नीति के कार्यान्वयन पर यथावश्यक बल देने के लिए खाद्य एवं पोषण बोर्ड (सलाहकार समिति) तथा पोषण नीति से संबंधित अंतरमंत्रालयी समन्वय समिति का विलय करके दिनांक 20 अक्टूबर, 1997 के संकल्प संख्या 6-2/96-एन.डी.-I/टैक के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने खाद्य एवं पोषण परिषद् का गठन किया गया। इस परिषद् का कार्यकाल इसके गठन से तीन वर्ष की अवधि के लिए था। खाद्य एवं पोषण परिषद् का कार्यकाल समाप्त होने पर उसका पुनर्गठन नहीं किया गया।

पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा को किसी देश के मानव संसाधनों के विकास की महत्वपूर्ण शर्त के रूप में अधिकाधिक मान्यता मिल रही है। पोषण शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य एक व्यक्ति को उसके शरीर की पोषाहारीय जरूरतों तथा जिस क्षेत्र में वह रहता है, उस क्षेत्र के खाद्य संसाधनों और सांस्कृतिक पद्धति के अनुरूप भोजन संबंधी आदतें विकसित करने में सहायता प्रदान करना है। पोषण शिक्षा न केवल खाद्य पदार्थों के पोषण संबंधी महत्व की जानकारी प्रदान करने, अपितु लोगों को स्वयं अपने और अपने परिजन की पोषाहारीय एवं

स्वास्थ्य देख-रेख के लिए ज्ञान का भ्रत बनाने की प्रक्रिया भी है। जनसमुदाय को पोषण शिक्षा प्रदान करने का दीर्घकालीन प्रभाव देखने को मिलता है।

मौजूदा परिस्थितियों में खाद्य एवं पोषण बोर्ड सलाहकार समिति को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि यह समिति सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से संबंधित कुपोषण सहित कुपोषण के स्तर में तेजी से कमी लाने तथा बेहतर स्वास्थ्य, कार्य क्षमता और तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियां तैयार कर सकें और सरकार को सलाह दे सकें।

II. खाद्य एवं पोषण बोर्ड की भूमिका और दायित्व.—चूंकि, कुपोषण बहुआयामी समस्या है, इसलिए इसके निवारण एवं नियंत्रण हेतु बहु-विषयक एवं बहु-उद्देश्यीय कार्रवाई की जरूरत है। पोषाहारीय सरोकारों को विकास प्रक्रिया में शामिल करना जन सामान्य का इष्टतम पोषण सुनिश्चित करने का सर्वाधिक कारगर साधन है तथा राष्ट्रीय पोषण नीति में भी मुख्यतः इसी साधन पर जोर दिया गया है। वर्ष 1992 में रोम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पोषण सम्मेलन में चयनित 9 विषयों में भी पोषण के विकास नीतियों एवं कार्यक्रमों में समावेश को शामिल किया गया था।

खाद्य एवं पोषण बोर्ड विभिन्न क्षेत्रों के पोषणोन्मुख कार्यक्रमों का अवलोकन करने वाले तथा पोषण संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर नीतिगत दिशानिर्देश जारी करने वाले मंच की भूमिका अदा करेगा। खाद्य एवं पोषण बोर्ड आगे दर्शाए गए विषयों के संबंध में सरकार को सलाह देगा तथा कार्यक्रमों का आयोजन, संवर्धन एवं समन्वयन करेगा, ताकि सभी क्षेत्रों में लिए जा रहे प्रयासों को कुपोषण के उन्मूलन और विकास प्रक्रिया में तेजी लाने के सामान्य उद्देश्य की ओर बढ़ाया जा सके :

- (i) नीति-निर्माताओं और कार्यान्वयनकर्ताओं के समर्थन एवं संचेतना के माध्यम से पोषण संबंधी मुद्दों को विकास प्रक्रिया के केंद्र में लाना।
- (ii) सभी स्तरों पर कुपोषण के निवारण और नियंत्रण के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाना।
- (iii) लोगों के पूरे जीवन उनकी पोषाहारीय एवं स्वास्थ्य स्थिति को प्रभावित करने वाली शिशुओं एवं छोटे बच्चों के पोषण से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना।
- (iv) खाद्य संपुष्टीकरण उपायों को यथोचित महत्व देते हुए सघन कार्यक्रम चलाकर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से संबंधित कुपोषण में कमी की प्रक्रिया में तेजी लाना।
- (v) पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यावसायिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के सहयोग से पोषण संबंधी मौजूदा कार्यक्रमों की विषय-वस्तु और सेवाओं में सुधार करना।
- (vi) ऐसे अन्य मामले, जिन्हें बोर्ड उपर्युक्त उद्देश्यों से संबंधित अथवा उनकी प्राप्ति के लिए अनुकूल माने।

III. संरचना.—खाद्य एवं पोषण बोर्ड (सलाहकार समिति) की संरचना इस प्रकार होगी :

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, —अध्यक्ष
भारत सरकार
2. संयुक्त सचिव, बाल विकास एवं पोषण, —सदस्य
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
भारत सरकार (पोषण प्रभारी)
3. वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास —सदस्य
मंत्रालय, भारत सरकार
4. सलाहकार (पोषण), डी.जी.एच.एस., स्वास्थ्य —सदस्य
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
5. सलाहकार (पोषण स्वास्थ्य और परिवार —सदस्य
कल्याण), योजना आयोग
6. महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान —सदस्य
परिषद्, नई दिल्ली
7. निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद —सदस्य
8. निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान —सदस्य
संस्थान, मैसूर
9. निदेशक, रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, —सदस्य
रक्षा मंत्रालय, मैसूर
10. सलाहकार (खाद्य एवं पोषण) जैव-प्रौद्योगिकी —सदस्य
विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
ब्लॉक-2, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श —सदस्य
सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली
12. प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन, अध्यक्ष एम. एस. —सदस्य
स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान, चेन्नई
13. डॉ. सी. एस. पाण्डव, प्रो. एवं अध्यक्ष, —सदस्य
सैंटर फॉर कम्युनिटी मैडिसिन, अखिल
भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
14. डॉ. अनुरा कुरपट, (क्लिनिकल न्यूट्रिशियन), —सदस्य
डीन, सेंट जोन्स मैडिकल कॉलेज, बेंगलूर
15. डॉ. एच.पी.एस. सचदेवा (क्लिनिकल —सदस्य
न्यूट्रिशियन), सीताराम भारतीय अस्पताल,
(भूतपूर्व शिशु रोग विभागाध्यक्ष, मौलाना
आजाद मैडिकल कॉलेज, नई दिल्ली);
नई दिल्ली
16. तकनीकी सलाहकार, खाद्य एवं पोषण बोर्ड, —सदस्य
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
भारत सरकार

अध्यक्ष केन्द्र अथवा राज्य सरकारों से किसी अन्य अधिकारी अथवा गैर-सरकारी व्यक्ति को खाद्य एवं पोषण बोर्ड की किसी भी बैठक में शामिल कर सकते हैं। बोर्ड जैसा आवश्यक समझे समय-समय पर ऐसी समितियाँ गठित कर सकेगा तथा इन समितियों को यथावश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगा।

IV. बोर्ड का दर्जा और शक्तियाँ.—खाद्य एवं पोषण बोर्ड वित्तीय, प्रशासनिक और अन्य मामलों के संबंध में केन्द्र सरकार के विभाग की शक्तियों का प्रयोग करेगा और बोर्ड में गैर-सांविधिक, उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति होगी। विभाग की वित्तीय शक्तियों से बाहर किसी मामले के संबंध में वित्त मंत्रालय की सहमति की आवश्यकता होने पर सदस्य (वित्त) वित्त मंत्रालय की ओर से सहमति प्रदान करेगा।

V. बोर्ड का सचिवालय और कार्यकारी शाखा.—बोर्ड के सचिवालय और कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के विभाग की गैर-योजना अवसंरचना सहित मौजूदा खाद्य एवं पोषण बोर्ड में उपयुक्त रूप से सुधार व इसका पुनर्गठन किया जाएगा। तकनीकी सलाहकार इस बोर्ड के सदस्य-सचिव होंगे और खाद्य एवं पोषण बोर्ड के अधिकारी तथा यथावश्यक अन्य कर्मचारी उनकी सहायता करेंगे।

VI. कार्य संचालन.—खाद्य एवं पोषण बोर्ड (सलाहकार समिति) की बैठक सामान्यतः वर्ष में दो बार अथवा आवश्यकता के अनुसार इससे अधिक बार आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में बोर्ड सभी योजनाओं एवं कार्यनीतियों के तकनीकी मुद्दों तथा पोषाहारीय पहलुओं के संबंध में विचार-विमर्श करेगा। अपने कार्यों के संचालन के मामले में बोर्ड सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन करेगा।

VII. बोर्ड के निर्णय और आदेश.—बोर्ड के निर्णयों, आदेशों, स्वीकृतियों, अनुदेशों आदि की सूचना बोर्ड के सदस्य-सचिव अथवा इस प्रयोजनार्थ विभाग द्वारा विधिवत् नामित अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी की जाएगी।

VIII. बजट.—बोर्ड की बैठकों में इसके सदस्यों की भागीदारी तथा बोर्ड के विभिन्न कार्यकलापों पर किए जाने वाले व्यय की पूर्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड के कुल बजट से की जाएगी।

IX. कार्यकाल.—खाद्य एवं पोषण बोर्ड (सलाहकार समिति) का कार्यकाल राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष का होगा।

प्रदीप बोलीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(Food and Nutrition Board)

RESOLUTION

New Delhi, the 14th March, 2008

No. 6-5/2005-ND/Tech.—I. Preamble.—Nutritional status is internationally recognized as an indicator of national development. Nutrition is both an input into and an output of the development process. A well nourished,

healthy workforce is a pre-condition for successful economic and social development, and as such food security, nutrition, health and sanitation are a responsibility of all development sectors.

India has a long standing and proud record of nutrition research and yet from all accounts India's burden of chronic, endemic malnutrition and ill health continues to be unabated. A number of nutrition interventions are being implemented in the country by different sectors which have direct and indirect impact on the nutritional status of the people, yet the country has unacceptably high malnutrition levels particularly in the vulnerable groups comprising of young children, expectant and nursing mothers. Varying degrees of malnutrition in these age groups influence morbidity and mortality rates in the country adversely affecting development of the country. Thus, nutrition emerges as one of the most important prerequisites for national development.

The Government of India had constituted the Food and Nutrition Board (FNB) in 1964 in the Ministry of Agriculture, vide Resolution No.6(10)/63-Tech.I dated 24-4-1964, with all the powers of a Central Government Department (Ministry of Finance, Department of Expenditure, Dy. No 2003-JS (F&A)/64 dated 20th May, 1964), for securing an accelerated, coordinated and effective implementation of the programmes of the development and popularization of subsidiary and protective foods; nutrition, food extension and food management; food preservation, processing and matters incidental or conducive to attainment of nutritional objectives. The Food and Nutrition Board (non-plan infrastructure) was transferred from the Ministry of Food and Agriculture to the Ministry of Human Resource Development, Department of Women and Child Development in 1993.

The FNB has been reconstituted from time to time and its functions redefined according to the needs of that time. In order to provide the necessary thrust to the implementation of the National Nutrition Policy, a Food and Nutrition Council was constituted in the Department of Women and Child Development, vide resolution No. 6-2/96-ND.I/Tech dated 20th October, 1997, by amalgamating the Food and Nutrition Board (advisory committee) and Inter-ministerial Coordination Committee on Nutrition Policy. The tenure of the Council was for three years from the date of its constitution. The Food and Nutrition Council was further not constituted on expiry of its tenure.

Nutrition and Health Education are increasingly being recognized as important prerequisites for development of human resources of a country. The fundamental objective of Education in Nutrition is to help individual to establish food habits and practices that are consistent with nutritional needs of the body and adapted to the cultural pattern and food resources of the area in

which they live. Nutrition Education is not merely a process of transferring facts or information about nutritive value of foods but also equipped the people with their own knowledge resource to take nutritional and health care of themselves and their family members. Imparting Nutrition Education to the masses has its long term sustainable impact.

Under the prevailing circumstances, it has been decided to revive and reconstitute the Food and Nutrition Board advisory committee so that it could work out policies, advise Government and promote activities for accelerating reduction in malnutrition levels including micronutrient malnutrition and promoting better health, productivity and faster economic growth.

II. Role and Responsibility of the Food and Nutrition Board.—The problem of malnutrition being multifaceted in nature requires a multi-disciplinary and multi-pronged action for its prevention and control. Integrating nutritional considerations into the development process is one of the most efficient and effective means of ensuring optimum nutrition for the people and has been the main thrust of the National Nutrition Policy. Incorporation of nutrition into development policies and programmes was also one of the nine themes selected by the International Conference of Nutrition (ICN) held in Rome in 1992.

The Food and Nutrition Board will provide a forum to oversee the implementation of various nutrition oriented sectoral interventions and to issue policy guidelines on nutritional issues of critical importance. The Food and Nutrition Board will advise the Government and undertake, promote and coordinate activities in regard to the following so that all sectoral efforts converge towards the common aim of elimination of malnutrition and accelerating the development process :

- (i) Bringing nutrition issues centre stage through advocacy and sensitisation of policy planners and implementers.
- (ii) Launching a vigorous awareness campaign on prevention and control of malnutrition at all levels.
- (iii) Addressing infant and young child nutrition issues which determine nutrition and health status of the people for their whole life.
- (iv) Accelerating reduction in micronutrient malnutrition through intensified programmes giving due focus to food fortification measures.
- (v) Improving content and delivery of existing nutrition related interventions enlisting cooperation of professional institutions and social organisations in the area of nutrition and health.

- (vi) Such other matters as the Board may consider incidental or conducive for attainment of above objectives.

III. Composition.—The Composition of the Food and Nutrition Board (advisory committee) will be as follows :

1. Secretary, Ministry of Women & Child Development, GOI. —Chairman
2. Joint Secretary, Child Development and Nutrition, MWCD, GOI (In-charge Nutrition). —Member
3. Financial Adviser, Ministry of Women and Child Development, GOI. —Member
4. Adviser (Nutrition), DGHS, Ministry of Health and Family Welfare. —Member
5. Adviser, (Nutrition Health and Family Welfare), Planning Commission. —Member
6. Director General, Indian Council of Medical Research, New Delhi. —Member
7. Director, National Institute of Nutrition, Hyderabad. —Member
8. Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore. —Member
9. Director, Defence Food Research Laboratory, Ministry of Defence, Mysore. —Member
10. Advisor (Food and Nutrition), Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Block-2, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi. —Member
11. Chief Executive Officer, National Sample Survey Organisation New Delhi. —Member
12. Prof. M.S. Swaminathan, Chairman, M.S. Swaminathan Research Foundation, Chennai. —Member
13. Dr. C.S. Pandav, Prof. and Head, Centre for Community Medicine, AIIMS, New Delhi. —Member
14. Dr. Anura Kurpat (Clinical Nutrition), Dean, St. Johns Medical College, Bangalore. —Member
15. Dr. H.P.S. Sachdeva, (Clinical Nutrition), Sita Ram Bhartiya Hospital (Former Prof. of Paediatrics, Maulana Azad Medical College, New Delhi), New Delhi. —Member

16. Technical Adviser, Food and Nutrition Board Ministry of Women and Child Development, GOI. —Member Secretary

The Chairman may co-opt any other official(s) from Centre or State Governments or non-official(s) as member(s) of the Food and Nutrition Board for any of its meetings. The Board may constitute such committees as it may deem necessary from time to time and delegate such powers to these Committees, as it may consider appropriate.

IV. Status and Powers of the Board.—The Food and Nutrition Board will exercise powers of a Department of Central Government, with regard to financial, administrative and other matters and will have a non-statutory high-powered advisory committee. In respect of matters exceeding the financial powers of a Department and requiring the concurrence of the Ministry of Finance, the Member (Finance) shall communicate the concurrence on behalf of the Ministry of Finance.

V. Secretariat and Executive Arm of the Board.—The existing Food and Nutrition Board, with its non-plan infrastructure of a department of the Ministry of Women and Child Development will be suitably strengthened and reorganized to serve as the secretariat and the executive arm of

the Board. The Technical Adviser will be the Member Secretary of the Board and will be assisted by the officers of Food and Nutrition Board and such other staff as may be found necessary.

VI. Transaction of Business.—The Food and Nutrition Board (Advisory Committee) would normally meet twice a year or more frequently as per the need. The Board will discuss the technical issues and nutritional aspects of all the plans and strategies. In exercise of its functions, the Board shall be subject to such directions and instructions as Government may issue from time to time.

VII. Decision and Orders of the Board.—The Board's decisions, orders, sanctions, instructions etc. shall be communicated under the signatures of the Member Secretary of the Board or any other officer of the Department duly nominated for this purpose.

VIII. Budget.—The expenditure on various activities of the Board, on participation of Members in its meetings will be met from the total budget of the Food and Nutrition Board of the Ministry of Women and Child Development.

IX. Tenure.—The tenure of the Food and Nutrition Board (advisory committee) will be three years with effect from the date of publication of this Resolution in the Gazette.

Ms. PRADEEP BOLINA, Jt. Secy.

993 GI/08-2